Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding Implementation of Revamped Distribution Sector Scheme(RDSS) in Churu Parliamentary Constituency

श्री राहुल कस्वां (चुरू): सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा पावर मंत्रालय के माध्यम से जुलाई, 2000 में एक नई स्कीम लांच की गई थी। ... (व्यवधान) इस स्कीम का नाम रिवैम्प डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म स्कीम है।... (व्यवधान) इसमें बजट का प्रावधान लगभग 300,000 करोड़ रुपये के आस-पास है। ... (व्यवधान) इस स्कीम का मकसद यही था कि राज्यों के अंदर पावर सैक्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज़ हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए पैसा खर्च किया जाए। ... (व्यवधान) सर, मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि राजस्थान सरकार को भी इस स्कीम के तहत साढ़े 8,000 करोड़ रुपये का बजट सैंक्शन हुआ, परंतु जुलाई, 2000 की लांच हुई स्कीम आज तक राजस्थान में पूरी तरह लागू नहीं हुई है। इस स्कीम का एक बहुत बड़ा पार्ट यह भी था कि इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट इलैक्ट्रिसिटी किमेटी बनानी थी, जिसका अध्यक्ष एक सांसद होता है, वह आज तक गठित नहीं की गई है।

सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू के अंदर पूरी जो एक बेल्ट है – सरदारशहर, सुजानगढ, बिदाशर, रोहतंगढ, जिसके अंदर बिजली की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि वहां कुएं बहुत ज्यादा बन गए हैं, हम एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। परंतु परेशानी यह है कि इस स्कीम के लिए हमारे पास बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके लिए 33केवीए के जीएसएस चाहिए, 32केवीए के सब-स्टेशंस चाहिए। परंतु सरकार के पास कोई नीति नहीं है। हाल ही में लूनासर गांव जो सरदारशहर के अंदर है, वह 5 दिन अंधेरे में रहा, क्योंकि सैक्टर के रिफॉर्म पर काम नहीं हुआ और सरकार नए-नए कनेक्शंस देती जा रही है। सर, यही नहीं, राजस्थान हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा राज्य होगा, जिसके पास अपनी ढ़ाड़ियों में बैठे हुए एक आखिरी व्यक्ति को देने के लिए कोई योजना नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में ही 18,000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी के नए कनेक्शंस की मांग है। राज्य सरकार सोई हुई है।

सर, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस महत्वपूर्ण योजना को लागू किया जाए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि डीईसी बनाने का काम जल्द से जल्द हो, वही एक प्लान बनाएगी कि कहां-कहां पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राजस्थान सरकार को बाध्य किया जाए और साढ़े 8,000 करोड़ रुपये जो भारत सरकार ने दिए हैं, उसके उपयोग करने के निर्देश दिए जाएं।